



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 74]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 29, 2017/चैत्र 8, 1939

No. 74]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 29, 2017/CHAITRA 8, 1939

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली 28 मार्च, 2017

प्रकरण सं OI/20/2017

(नई जाँच)

विषय : चीन जन. गण. और इंडोनेशिया के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'ग्लासवेयर' के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जाँच

फा. सं. 14/45/2016-डीजीएडी.—(1) यतः मै. श्रेनो लिमिटेड – ग्लास डिबीजन (जिन्हें आगे 'आवेदक' भी कहा गया है) ने सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष चीन जन. गण. और इंडोनेशिया (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) से ग्लासवेयर (जिसे आगे संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जाँच की शुरूआत करने और उन पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया है।

2. और यतः प्राधिकारी प्रथम दृष्टया यह पाते हैं कि पाटनरोधी जांच की शुरूआत को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति तथा कथित पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य हैं और प्राधिकारी एतद्वारा पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार कथित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति की जांच की शुरूआत करते हैं ताकि

कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई 'क्षति' को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

क. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

3. याचिकाकर्ता का यह आरोप है कि टेबल, रसोई, टायलेट, कार्यालय या इंडोर सजावट के प्रयोग के लिए सोडा लाइम ग्लासवेयर (बोरोसिलिकेट ग्लासवेयर और ओपेल ग्लासवेयर को छोड़कर) का पाटित कीमतों पर संबद्ध देशों से भारत को निर्यात किया जा रहा है जिससे भारत में घरेलू उद्योग का समान उत्पाद प्रभावित हो रहा है।

4. ग्लास एक गैर-क्रिस्टलीय, आकार रहित और सामान्यतः पारदर्शी ठोस सामग्री होता है जिसे सिलिका (रेत) से प्राथमिक रूप से बनाया जाता है जिसे अन्य अभिवर्द्धकों के अलग-अलग संघटकों से मिलाया जाता है। यह अभिवर्द्धक - जैसे चूना पत्थर, अलुमिना, डोलोमाइट और सोडा एश या बोरेक्स - विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए यथा वांछित भिन्न-भिन्न भौतिक और रासायनिक विशेषताएं बनाती हैं। 'ग्लासवेयर' शब्द सीसे से बनी किसी वस्तु या चीज को दर्शाता है। ग्लास और अन्य विशेषताओं के संघटन के आधार पर ग्लासवेयर को सोडा लाइम ग्लासवेयर, बोरोसिलिकेट ग्लासवेयर, ओपेल ग्लासवेयर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। आजकल, ग्लासवेयर का प्रयोग ताजे, पकाये हुए और संरक्षित खाद्य पदार्थ के भंडारण, बनाने, संरक्षण, पकाने और परोसने के लिए होटलों और घरों में लगातार बढ़ रहा है।

5. याचिकाकर्ता सोडा लाइम ग्लासवेयर का एक उत्पादक है जिसमें 'टेबल, रसोई, टायलेट, कार्यालय, इंडोर सजावट या समान प्रयोजनों के लिए' सभी प्रकार के टेबलवेयर, ड्रिंकवेयर, किचेनवेयर और गिफ्टवेयर, जो होटलों, रेस्टोरेंटों, केटरों, कार्पोरेट और घरेलू दीर्घावधिक प्रयोग -चाहे भंडारण हो या परोसना - में प्रयोग होते हैं, शामिल हैं। याचिकाकर्ता ने सोडा लाइम ग्लासवेयर के पाटन का आरोप लगाया है और यह दावा किया है कि उनके द्वारा उत्पादित और चीन और इंडोनेशिया से आयातित सोडा लाइम ग्लासवेयर के बीच कोई अंतर नहीं है।

6. अतः इस जाँच के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद (जिसे आगे संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) को निम्नानुसार परिभाषित किया जा रहा है:

7. 'टेबल, रसोई, टायलेट, कार्यालय या इंडोर सजावट के प्रयोग के लिए सभी प्रकार के सोडा लाइम ग्लासवेयर। विचाराधीन उत्पाद में बोरोसिलिकेट ग्लासवेयर और ओपेल ग्लासवेयर शामिल नहीं हैं। विचाराधीन उत्पाद में पैकेजिंग उद्योग के लिए प्रयोग की जाने वाली कवर ग्लास बोतलें शामिल नहीं हैं।

उत्पाद वर्गीकरण

8. संबद्ध वस्तु को 4 अंकीय स्तर पर उपशीर्ष 7013 के अधीन सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 70 के अधीन वर्गीकृत किया जाता है। ये उत्पाद आईटीसी एचएस 701329, 701337, 701339, 701349 और 701499 के अधीन शामिल हैं। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और जाँच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है। उत्पाद पर 10 प्रतिशत मूल शुल्क लगता है। तथापि, इंडोनेशिया के लिए यह उत्पाद रियायती शुल्कों वाले आसियान एफटीए के अधीन शामिल है।

ख. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

9. यह याचिका श्रेनो लिमिटेड -ग्लास डिवीजन द्वारा दायर की गई है। असंगठित क्षेत्र में अन्य उत्पादक हैं। याचिकाकर्ता के पास संबद्ध वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनता है। याचिकाकर्ता कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित नहीं है। याचिकाकर्ता ने संबद्ध देशों से पाटित वस्तुओं का आयात नहीं किया है। इसलिए आवेदक नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आवेदन दायर करने की योग्यता रखता है। चूंकि आवेदक के पास घरेलू उत्पादन में प्रमुख हिस्सा है इसलिए क्षति जाँच के प्रयोजनार्थ वह नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग है। तदनुसार आवेदन को घरेलू उद्योग द्वारा और उसकी ओर से दायर किया गया माना गया है।

ग. शामिल देश और निर्धारित न्यूनतम सीमा

10. यह याचिका चीन जन. गण. और इंडोनेशिया से ग्लासवेयर के पाटन के संबंध में है। इन देशों से आयातों की मात्रा विहित न्यूनतम सीमा से अधिक है। उक्त देशों के अलावा, यूरोपीय संघ और थाइलैंड से आयात हुए हैं जो कुल आयातों के 3 प्रतिशत से अधिक हैं। तथापि ये आयात गैर-पाटित और काफी अधिक कीमतों पर हुए हैं, जिससे घरेलू उद्योग प्रभावित नहीं हुआ है। तदनुसार, यह जाँच केवल चीन और इंडोनेशिया (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के संबंध में है।

घ. पाटन का साक्ष्य

11. याचिकाकर्ताओं ने बताया है कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु की घरेलू कीमतों के संबंध में सार्वजनिक डोमेन में विश्वसनीय सूचना के अभाव में संबद्ध देशों के लिए सामान्य मूल्य का अनुमान उन देशों में कच्ची सामग्रियों और सुविधाओं की प्रचलित कीमतों पर विचार करते हुए उत्पादन लागत, सबसे अधिक कार्यकुशल घरेलू उद्योग की परिवर्तन लागत और विधिवत रूप से समायोजित बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय जमा तर्कसंगत लाभ पर विचार करते हुए लगाया गया है।

12. संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तु की निवल कारखाना-द्वार निर्यात कीमत जाँच की प्रस्तावित अवधि के लिए डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त आयात आकड़ों के आधार पर अनुमानित की गई है जिसमें समुद्री भाड़ा और समुद्री बीमा, पत्तन व्यय, अंतरदेशीय भाड़ा, कमीशन और बैंक प्रभार और वैट समायोजन, जहां लागू हो को उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आवश्यक समायोजन किए गए हैं।

13. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के उक्त अनुमान से पता चलता है कि इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि भारत को संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का निर्यात काफी पाटित कीमतों पर किया जा रहा है और पाटन मार्जिन निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक हैं।

ङ. क्षति और कारणात्मक संबंध के साक्ष्य

14. आवेदकों ने दावा किया है कि उन्हें संबद्ध देशों से पाटित आयातों के मात्रा और कीमत के संचयी प्रभाव के कारण वास्तविक क्षति हुई है। याचिकाकर्ताओं द्वारा दी गई सूचना से पता चलता है कि जाँच की अवधि के दौरान पाटित आयातों की मात्रा में भारी वृद्धि हुई है और मांग और देश में क्षमता की उपलब्धता में मामूली वृद्धि के बावजूद घरेलू उद्योग का उत्पादन और क्षमता उपयोग बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। कीमत प्राप्ति भी बिक्री लागत से काफी कम रही है जिसका स्पष्ट कारण पाटित आयातों के मात्रा और कीमत प्रभाव रहे हैं जिनसे भारी वित्तीय घाटा हुआ है। इसलिए प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि आवेदक घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से पाटित आयातों के मात्रा और कीमत प्रभावों के कारण उत्पादन में कमी, ऋणात्मक लाभ और निवेशों पर ऋणात्मक आय के कारण वास्तविक क्षति हो रही है।

च. जाँच की शुरुआत

15. और यतः उक्त नियमावली को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी प्रथम दृष्टया यह पाते हैं कि पाटनरोधी जाँच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति तथा कथित पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध पर्याप्त साक्ष्य हैं इसलिए प्राधिकारी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव को निर्धारित करने और पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई 'क्षति' को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, के लिए जाँच की शुरुआत करते हैं। तदनुसार, प्राधिकारी एतद्वारा नियमावली के पैरा 5 के अनुसार कथित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति के संबंध में जाँच की शुरुआत करते हैं।

1. विचाराधीन उत्पाद

इस जाँच में विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

टेबल, रसोई, टायलेट, कार्यालय या इंडोर सजावट के प्रयोग के लिए सभी प्रकार के सोडा लाइम ग्लासवेयर। विचाराधीन उत्पाद में बोरोसिलिकेट ग्लासवेयर और ओपेल ग्लासवेयर शामिल नहीं हैं। विचाराधीन उत्पाद में पैकेजिंग उद्योग के लिए प्रयोग की जाने वाली कवर ग्लास बोतलें शामिल नहीं हैं।

ii. जाँच की अवधि (पीओआई)

16. इस जाँच के प्रयोजनार्थ जाँच अवधि अप्रैल 2015 से सितंबर, 2016 तक (18 महीनों) की है। क्षति जाँच अवधि में 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 और जाँच अवधि की अवधि शामिल होंगी।

iii. सूचना प्रस्तुत करना

17. संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावासों/प्रतिनिधियों के जरिए उनकी सरकारों, भारत में ज्ञात आयातकों व प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को अलग-अलग सूचित किया जा रहा है ताकि वे विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को नीचे दिए गए पते पर प्रस्तुत कर सकें जिससे प्राधिकारी समयबद्ध ढंग से समुचित निर्धारण कर सकें:

निर्दिष्ट प्राधिकारी
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य विभाग,
जीवन तारा बिल्डिंग, चौथा तल
संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001

dgad.india@gov.in

18. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत सूचना संबंधी कोई अनुरोध नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति (जो प्राधिकारी की वेबसाइट (www.dgtr.gov.in) से डाउनलोड किया जा सकता है) से प्रस्तुत कर सकता है।

iv. समय-सीमा

19. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस अधिसूचना की तारीख से दो सप्ताह के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के चालीस (40) दिनों के भीतर प्रश्नावली के अपने उत्तर और तथा घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें। यह सूचना हार्ड प्रति और साफ्ट प्रतियों में अवश्य प्रस्तुत की जानी चाहिए।

20. निर्यातकों/आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षों को इस सूचना के पत्र की तारीख से चालीस (40) दिनों के भीतर अपने उत्तर अलग-अलग प्रस्तुत करने के लिए अलग-अलग सूचित किया जा रहा है।

21. यह नोट किया जाए कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार, रिकार्ड में "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

v. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

22. प्रश्नावली के उत्तर सहित गोपनीय आधार पर प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उनके साथ संलग्न परिशिष्टों/अनुबंधों सहित) करने वाले पक्षकारों को किए गए अनुरोधों को अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना होगा। जिसे अन्य हितबद्ध पक्षों को उनकी टिप्पणियों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। उनकी मूल प्रति के साथ दो-दो (2) प्रतियों में दोनों अंशों की साफ्ट प्रतियां भी प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

23. दी गई समस्त सूचना पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

24. गोपनीय अंश में ऐसी समस्त सूचना हो सकती है जो स्वभाविक रूप से गोपनीय है और/या अन्य सूचना जिसे ऐसी सूचना का प्रदाता व्यापार संवेदी सूचना होने का दावा करता है जिसके प्रकटन से ऐसी सूचना के प्रदाता का वाणिज्यिक हित प्रतिकूलतः प्रभावित होंगे। स्वाभाविक रूप से गोपनीय और गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

25. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध/रिक्त छोड़ी गई और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है। सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

26. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

vi. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

27. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

vii. असहयोग

28. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

डॉ. इन्द्रजीत सिंह, अपर सचिव और निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2017

Case No. OI-20/2017

(Fresh Investigation)

Subject: - Anti-Dumping investigation concerning imports of “Glassware” originating in or exported from People’s Republic of China and Indonesia.

No. 14/45/2016-DGAD.—(1) Whereas M/s. Shreno Limited - Glass Division (hereinafter referred to as the applicant) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 (hereinafter also referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped articles and for Determination of injury) Rules, 1995 (hereinafter also referred to as the Rules) as amended from time to time,

for initiation of anti-dumping investigation and imposition of anti-dumping duty concerning imports of Glassware (also referred to as Subject goods) from People's Republic of China and Indonesia (also referred to as the Subject Countries).

2. And whereas, the Authority finds sufficient *prima facie* evidence of dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, 'injury' to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and 'injury' exists justifying initiation of an anti-dumping investigation, the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of Rule 5 of the Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to consider recommending an amount of antidumping duty, which if levied, would be adequate to remove the 'injury' to the domestic industry.

A. Product under consideration and Like Articles

3. The petitioner has alleged that Soda-lime Glassware for Table, Kitchen, Toilet, Office or Indoor Decoration purposes, (excluding Borosilicate Glassware and Opal Glassware) are being exported to India from the subject countries at dumped prices which is affecting the like product domestic industry in India.
4. Glass is a non-crystalline, amorphous and generally transparent solid material manufactured primarily from Silica (sand), which is combined with varying compositions of other additives. These additives - like lime stone, alumina, dolomite and soda ash or borax – impart different physical and chemical properties as desired for different applications. The term "Glassware" describes any article or object made of glass. Depending upon the composition of glass and other properties the glassware is classified as 'Soda lime glassware, Borosilicate glassware, Opal Glassware. Nowadays, glassware is being increasingly used in hotels and households for storage, preparation, preservation, cooking and serving of fresh, cooked and preserved food.
5. The petitioner is a producer of Soda Lime Glassware, which covers all type of tableware, drink ware, kitchenware and giftware "for table, kitchen, toilet, office, indoor decoration or similar purposes", for regular and long term use by hotels, restaurants, caterers, corporate and households – whether for storage or service. The petitioner has alleged dumping of only Soda lime glassware and has claimed that there is no difference between the soda lime glassware produced by them and imported from China and Indonesia.
6. Therefore, for the purpose of this examination the product under consideration (herein after also referred to as the subject goods) is being defined as follows:
7. "All types of Soda-lime Glassware for Table, Kitchen, Toilet, Office or Indoor Decoration purposes". The product under consideration excludes Borosilicate Glassware and Opal Glassware. The product under consideration also does not cover glass bottles used for packaging industry.

Product classification

8. Subject goods are classified under chapter 70 of Customs Tariff Act, 1975 under the sub-heading 7013 at 4-digit lev. The products are covered under ITC HS 701329, 701337, 701339, 701349 and 701499. The Custom classification is indicative only and not binding on the scope of investigation. The product attracts 10% basic duty. However, for Indonesia this product is covered under ASEAN FTA attaching concessional duties.

B. Domestic Industry & Standing

9. The petition has been filed by Shreno Limited - Glass Division. There are other producers in the unorganized sector. The petitioner commands a major proportion of the total domestic production of the subject goods. The petitioner is not related to the exporters or importers of the alleged dumped article. The petitioner has not imported the dumped articles from subject countries. Therefore, the applicant commands standing in terms of Rule 5 (3) of the Rules to file this application. Since the applicant commands a major proportion of the domestic production, it constitutes the domestic industry, within the meaning of the terms under Rule 2 (b), for the

purpose of injury investigation. Accordingly, the application is deemed to have been filed on behalf of the domestic industry.

C. Countries involved and de minimis limits

10. The petition is filed in respect of the dumping of the Glassware from People's Republic of China and Indonesia. The imports from the above countries are above de minimis limits. Apart from the above countries imports are also taking place from the European Union and Thailand which is above 3% of total imports. However, the imports are stated to be non-dumped and at higher prices, not affecting the domestic industry. Accordingly, the investigation is with respect to only China and Indonesia (hereinafter referred to as subject countries).

D. Evidence of Dumping

11. The petitioner has submitted that in the absence of availability of reliable information in the public domain on domestic prices of the subject goods in the subject countries the Normal values in the subject countries have been estimated on the basis of cost of production, taking into account prevailing prices of raw materials and utilities in those countries, conversion costs of the most efficient domestic industry, and duly adjusted selling, general & administration expenses, plus a reasonable profit.
12. Net ex-works export prices of the subject goods exported from the subject countries have been estimated on the basis of import data obtained from DGCI&S for the proposed period of investigation after due adjustments toward ocean freight and marine insurance; port expenses, inland freight, commission and bank charges; and VAT adjustments, wherever applicable on facts available basis.
13. The above estimation of the Normal Values and Export Prices indicates that there is sufficient *prima facie* evidence that the subject goods are being exported from the subject countries to India at significantly dumped prices and the dumping margins are above *de-minimis*.

E. Evidence of Injury and Causal Link

14. The applicant has claimed that they have suffered material injury because of cumulative volume and price impacts of the dumped imports from the subject countries. Information provided by the petitioners indicates that there has been significant rise in the volume of dumped imports during the period under examination despite moderation of demand in the country and availability of capacity in the country. The production and capacity utilization of the domestic industry has been significantly affected. The price realization also continues to be significantly below the cost of sales, apparently because of the volume and price effects of dumped imports leading to significant financial losses. Therefore, *prima facie* it appears that the applicant domestic industry is suffering material injury in terms of production loss, negative profits and negative return on investments due to the volume and price effects of the dumped imports from the subject countries.

F. Initiation of the Investigation

15. **And Whereas**, having regard to the above Rules, the Authority finds sufficient *prima facie* evidence of dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject countries; injury to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and injury, to justify initiation of an anti-dumping investigation to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which if levied, would be adequate to remove the 'injury' to the domestic industry. Accordingly, the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of Para 5 of the Rules.

i. Product under investigation

The product under investigation is defined as follows:

"All types of Soda-lime Glassware for Table, Kitchen, Toilet, Office or Indoor Decoration purposes". The product under consideration excludes Borosilicate Glassware and Opal Glassware. The product under consideration also does not cover glass bottles used for packaging industry.

ii. Period of Investigation (POI)

16. The period of investigation for the present investigation is from April 2015- September 2016 (18 months). The injury investigation period shall cover the periods 2012-13, 2013-14, 2014-15 and the period of investigation.

iii. Submission of Information

17. The known producers/exporters in the subject countries, their governments through their Embassies in India, the known importers and users in India, and the domestic industry are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address, so as to enable the Authority make appropriate determinations in a timely manner:

The Designated Authority

Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties

Department of Commerce,

Jeevan Tara Building, 4th Floor,

Parliament Street, New Delhi -110001

dgad.india@gov.in

18. Any other interested party may also make its submissions, relevant to the investigation, in the prescribed form and manner (downloadable from the website of the Authority at www.dgtr.gov.in) within the time limit set out below.

iv. Time Limit

19. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter within 2 weeks from the date of this notification and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application within forty days (40 days) from the date of publication of this Notification. The information must be submitted in hard copies as well as soft copies.
20. The exporters/importers and other interested parties, being notified individually may file their responses within forty days (40 days) from the date of the letter of intimation to be addressed to them separately.
21. It may be noted that if no information is received from an interested party within the prescribed time limit, or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record, in accordance with the Rules.

v. Submission of information on confidential basis

22. The parties making any submission (including Appendices/Annexure attached thereto), before the authority, including questionnaire response on confidential basis, are required to file a non-confidential version of the submissions made, which will be made available to all other interested parties to make their comments. Soft copies of both the versions will also be required to be submitted, along with the hard copies, in two (2) sets of each.
23. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked so at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
24. The confidential version may contain all information which are by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as business proprietary information, disclosure of which will adversely affect the commercial interest of the supplier of such information. For information which is claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

25. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out. In case indexation is not feasible, the information may be summarized, depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority
26. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted, or if the supplier of the information is either not willing to make the information public, or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information. The Authority, on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

vi. Inspection of Public File

27. In terms of Rule 6(7) of the AD Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by all interested parties to the investigation.

vii. Non-cooperation

28. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available with it and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

Dr.INDER JIT SINGH, Addl. Secy. & Designated Authority